RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 315
दि. 19.03.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का एआई सेक्टर के युवा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठा दृष्टिकोण

- मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों के उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया
- मुख्यमंत्री निवास परिसर में युवा स्टार्टअप के प्रोडक्ट की प्रदर्शनी देखी
- गुजरात को एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल सेंटर बनाने की दिशा में राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बहुआयामी आयोजन
- गुजरात एआई टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- मुख्यमंत्री ने शासन में पारदर्शिता और नागरिकों की खुशहाली के लिए एआई टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करने की गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की
- युवा स्टार्टअप्स ने गुजरात सरकार की युवा प्रोत्साहक कार्यपद्धति की खुले मन से प्रशंसा की
- राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दो महत्वपूर्ण एएमयू पर हस्ताक्षर किए
- सर्वम एआई गुजरात में एक आधुनिक सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करेगा
- स्टार्टअप को एआई सॉल्यूशन के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल की घोषणा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बुधवार को गांधीनगर में स्टार्टअप संवाद का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। यह संवाद गुजरात को युवा स्टार्टअप्स के स्केलेबल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस के जरिए और अधिक सक्षम बनाकर एआई और उभरती टेक्नोलॉजी (इमर्जिंग टेक्नोलॉजी) के लिए ग्लोबल सेंटर बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने इस स्टार्टअप संवाद में देश के विभिन्न राज्यों के 24 उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स के साथ प्रत्यक्ष संवाद-बातचीत की और उनके अनुभवों एवं नवाचारों (इनोवेशन) के बारे में जानने की काफी उत्सुकता दिखाई। स्टार्टअप्स के साथ इस संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के विकास की जो मजबूत नींव रखी थी, उसके चलते आज गुजरात वित्तीय अनुशासन के साथ नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। इतना ही नहीं, राज्य एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन ग्रोथ जैसे इमर्जिंग सेक्टर के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस संवाद के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई टेक्नोलॉजी के विभिन्न उपयोग से संबंधित 5 स्टार्टअप, हेल्थ सेक्टर में 3 और शिक्षा के विभिन्न आयामों पर एआई आधारित कार्य करने वाले 6 तथा सरकारी और उद्योग क्षेत्र के 10 स्टार्टअप ने मुख्यमंत्री और अन्य महानुभावों के समक्ष अपने कामकाज और प्रोडक्ट पर प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की मंशा ऐसे प्रतिभाशाली स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देने की है, जो सरकार के साथ काम करने को उत्सुक हैं, ताकि नवाचार और नए उद्यमियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि एआई के उपयोग से सरकारी कामकाज की गति को और बढ़ाना, कार्य में और पारदर्शिता लाना और सरकारी योजनाओं का लाभ

टेक्नोलॉजी के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की खुशहाली और सरकार की कार्यदक्षता बढ़ाने वाले प्रत्येक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए तत्पर है, लेकिन इस विजन को साकार करने के लिए सभी का प्रयास और दिशा एक होनी बहुत ही जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेक्नोलॉजी-आधारित विकास में 'क्वालिटी' राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता रहेगी। राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस एआई संवाद के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सर्वम एआई तथा माइको (MIKO) स्टार्टअप के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गुजरात की पेमेंट मोडालिटीज (भुगतान के तरीके या माध्यम) का भी लोकार्पण किया गया।

इस एमओयू के अंतर्गत सर्वम एआई द्वारा गुजरात में एक आधुनिक संप्रभु (सॉवरेन) एआई पार्क स्थापित किया जाएगा। इस एआई पार्क में एआई के लिए आवश्यक हाई-एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इनोवेशन के लिए सेंटर्स, युवाओं के लिए कौशल विकास, सरकार के लिए एआई-आधारित सॉल्यूशंस, नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी जैसी सारी सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएंगी। राज्य सरकार और सर्वम एआई के बीच हुए इस एमओयू के परिणामस्वरूप अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा एआई और नई टेक्नोलॉजी का एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा होगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी सेवाएं और भी स्मार्ट एवं तेज होंगी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार तेजी से आवश्यक अनुमतियां और क्लीयरेंस देगी। साथ ही, राज्य की नीतियों के अनुसार सहायता और सपोर्ट देगी तथा संबंधित विभागों के साथ तालमेल स्थापित कर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने एआई इनोवेशन चैलेंज के तहत स्टार्टअप्स को नए एआई सॉल्यूशंस विकसित करने और उन्हें तेजी से क्रियान्वित करने के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल घोषित किया है। इस पहल से स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) विकास से लेकर प्रोडक्शन रोलआउट तक के सभी चरणों में मजबूत आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे राज्य में हाई-इम्पेक्ट एआई-आधारित समाधानों को तेजी से लागू किया जा सकेगा। इस पहल के अंतर्गत पीओसी चरण के लिए स्टार्टअप्स को यूज केस के अनुसार सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मॉडरेट यूज केस के लिए 75 लाख रुपए तक और कॉम्प्लेक्स यूज केस के लिए 10 लाख रुपए तक की फंडिंग स्टेप-बाइ-स्टेप दी जाएगी। इस स्कीम के तहत स्टार्टअप का चयन होने के बाद 25 फीसदी राशि तुरंत दी जाएगी, जबकि सफल पीओसी पूरा होने के बाद बाकी की 75 फीसदी राशि दी जाएगी।

पीओसी सफल होने के बाद चुने हुए प्रोजेक्ट्स को फुल-स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए अधिक सपोर्ट-सहायता मिलेगी। मॉडरेट प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए तक और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सहायता फुल-स्केल डिप्लॉयमेंट, इंप्लिमेंटेशन, कस्टमाइजेशन, फीचर एन्हांसमेंट तथा हैंडहोल्डिंग सपोर्ट के लिए दी जाएगी। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को 4 वर्षों तक सपोर्ट मिलेगा, जिसके तहत गुजरात स्टेट डेटा सेंटर और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाया जा सकता है। इस फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल से स्टार्टअप्स को गुजरात सरकार के साथ सीधे काम करने का अवसर मिलेगा। राज्य को भी हाई-इम्पेक्ट एआई सॉल्यूशंस के तेजी से क्रियान्वयन, सरकारी सेवाओं में अधिक कार्यक्षमता और पारदर्शिता, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और गुजरात को एआई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने जैसे लाभ प्राप्त होंगे। यह पहल राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस को एक नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री ने युवा स्टार्टअप को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि इस संवाद से राज्य की विकास प्राथमिकताओं और सुशासन की जरूरतों को समझने के साथ-साथ उसके अनुरूप नवीन टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप सपोर्ट के लिए देश भर के ऐसे स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य पूरा होगा।

इतना ही नहीं, यह संवाद एआई, ड्रोन, हेल्थ एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में उभरते अवसरों के मूल्यांकन के जरिए राज्य सरकार के विभागों में कार्यदक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने में उपयुक्त साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इनोवेशन-लेड ग्रोथ के विजन के साथ गुजरात को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के व्यापक कार्यान्वयन और परिणाम आधारित पद्धति के लिए तैयार करने की नई दिशा इस स्टार्टअप संवाद से खुली है।

इस अवसर पर उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश कुमार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती ने गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम और विद्यार्थियों से लेकर स्टार्टअप्स तक, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, अपर मुख्य सचिव श्री आर.सी. मीणा, श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अजय कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) श्री अतुल गोर और निदेशक (आईटी और ई-गवर्नेंस) सुश्री कविता शाह सहित विभिन्न क्षेत्रों के युवा स्टार्टअप्स मौजूद रहे।

विधानसभा में नारे बनाम मुद्दे की टकराहट, 'जीरामजी' से भड़की सियासत और 'जय श्रीराम' से गूंजा सदन

(जीएनएस)। मुंबई की सियासत उस वक्त गरमा गई, जब महाराष्ट्र विधानसभा में एक गंभीर जनहित का मुद्दा अचानक तीखी राजनीतिक टकराहट में बदल गया। बुधवार, 18 मार्च 2026 को प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा मजदूरों के बकाया वेतन पर चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में यह बहस शब्दों के विवाद और नारों की जंग में तब्दील हो गई। शिवसेना विधायक भास्कर जाधव और भाजपा विधायक देवयानी फरांदे के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए पूरी तरह बाधित कर दिया। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब भास्कर जाधव ने मनरेगा मजदूरों के 3-4 साल से लंबित वेतन का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किया कि आखिर गरीब और मेहनतकश लोगों का पैसा इतने लंबे समय तक क्यों रोका गया है। उनके अनुसार यह केवल प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि उन परिवारों के जीवन पर सीधा असर डालने वाला गंभीर मुद्दा है, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए इसी आय पर निर्भर हैं। इसी दौरान सरकारी आदेशों यानी 'जीआर' (Government Resolution) का जिक्र करते हुए जाधव ने हल्के व्यंग्य में 'जीरामजी' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या सरकार ने लोगों से 'जय श्रीराम' कहलवाने का ठेका ले लिया है। यह टिप्पणी जैसे ही सदन में गूंजी, माहौल अचानक बदल गया और सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। जाधव के इस बयान से नाराज होकर देवयानी फरांदे ने अपनी सीट छोड़ दी और सीधे पहली पंक्ति में जाकर बैठ गईं। वहां से उन्होंने जाधव के भाषण में लगातार हस्तक्षेप करते हुए उनसे 'जय श्रीराम' बोलने की मांग की। उनके इस रुख से सदन का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया, और बहस का स्वर तेज हो गया। कुछ ही क्षणों में सदन में शोर-शराबा बढ़ गया और कार्यवाही बाधित होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सख्त लहजे में देवयानी फरांदे को उनकी मूल सीट पर लौटने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि सदन के नियमों का पालन सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पहली पंक्ति में आकर बैठने का मतलब यह नहीं कि किसी को वहां बैठने का अधिकार मिल जाता है। अध्यक्ष की फटकार के बाद कुछ समय के लिए स्थिति नियंत्रित जरूर हुई, लेकिन राजनीतिक तल्खी बनी रही।

इस बीच भास्कर जाधव ने भी अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने फरांदे के हस्तक्षेप पर पलटवार करते हुए कहा कि वे इतनी 'विद्वान' हैं कि उन्हें समझ पाना उनके लिए संभव नहीं है। इस बयान ने माहौल को और अधिक गर्म कर दिया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए।

पश्चिम एशिया संकट में भारत का बड़ा मानवीय अभियान, 2.6 लाख नागरिकों की सुरक्षित वापसी ने दिखाया भरोसा और ताकत

(जीएनएस)। पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक व्यापक और संगठित अभियान चलाया है। इस संकट के दौरान अब तक करीब 2.6 लाख भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है, जो न केवल सरकार की तत्परता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती जिम्मेदारी और क्षमता का भी प्रमाण है। यह अभियान ऐसे समय में चलाया गया जब क्षेत्र में अस्थिरता, उड़ानों पर असर और सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई थी।

पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के साथ ही हजारों भारतीय नागरिक, जिनमें कामकाजी पेशेवर, मजदूर, छात्र और पर्यटक शामिल थे, असमंजस की स्थिति में आ गए थे। ऐसे में भारत सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए अपने दूतावासों और संबंधित एजेंसियों को सक्रिय कर दिया। 28 फरवरी से शुरू हुई यह वापसी प्रक्रिया अब एक बड़े मानवीय अभियान का रूप ले चुकी है, जिसमें हर स्तर पर समन्वय और संवेदनशीलता देखने को मिली है।

विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस पूरे अभियान के दौरान स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार रणनीति में बदलाव भी किया जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और फ्लाइट सेवाएं भी क्रमशः बहाल की जा रही हैं। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिए बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों की वापसी प्रक्रिया को गति मिली है। इस पूरे अभियान में भारतीय दूतावासों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने न केवल फंसे हुए नागरिकों से संपर्क बनाए रखा, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और मानसिक रूप से सहयोग देने का भी कार्य किया। खासतौर पर छात्रों की सहायता के लिए विशेष प्रयास किए गए, क्योंकि वे अक्सर स्थानीय परिस्थितियों से कम परिचित होते हैं और अचानक उत्पन्न संकट में अधिक असहाय महसूस करते हैं।

यह पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह के संकट में अपने नागरिकों की मदद के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। इससे पहले भी विभिन्न देशों में उत्पन्न आपात स्थितियों के दौरान भारत ने बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाए हैं और हर बार अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता हासिल की है। इस बार भी वही प्रतिबद्धता और दक्षता देखने को मिली है, जिसने लाखों परिवारों को राहत की सांस दी है।

इस अभियान की सफलता का एक बड़ा कारण सरकार और एयरलाइंस के बीच बेहतर समन्वय भी रहा है। जैसे-जैसे हालात में सुधार हो रहा है, वैसे-वैसे उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। साथ ही, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि उनकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके।

राज्यसभा में विदाई के बीच भावुक हुए प्रधानमंत्री बोले-राजनीति में कभी नहीं लगता 'पूर्ण विराम'

(जीएनएस)। नई दिल्ली में लोकतंत्र के उच्च सदन का माहौल उस समय भावनाओं से भर गया, जब अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो रहे 59 सदस्यों को औपचारिक विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेरक और संवेदनशील संबोधन देते हुए न केवल विदा ले रहे सदस्यों के योगदान को सराहा, बल्कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन के मूल भाव को भी गहराई से समझाया। उनका संदेश साफ था—राजनीति में अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता और यहां 'पूर्ण विराम' जैसी कोई स्थिति नहीं होती।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संसद से विदाई को अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई सदस्य दोबारा चुनकर आए या समाज के अन्य क्षेत्रों में सेवा दे, लेकिन संसद में बिताए गए वर्षों का अनुभव देश के लिए हमेशा एक अमूल्य धरोहर बना रहता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "राजनीति में फुल स्टॉप जैसी कोई चीज नहीं होती," और यह वाक्य पूरे सदन में एक गहरी सोच छोड़ गया।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन वरिष्ठ नेताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिन्होंने दशकों तक संसदीय परंपराओं को मजबूत किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अनुभवी नेता शरद पवार की सराहना करते हुए कहा कि इन नेताओं ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संसद को समर्पित किया है। उनकी निरंतर उपस्थिति, अनुभव और व्यवहार नए सांसदों के लिए एक 'खुली किताब' की तरह हैं, जिससे सीखकर वे अपने सार्वजनिक जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री का संबोधन केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि उसमें हल्के-फुल्के और मानवीय पहलू भी शामिल थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को 'सदाबहार' बताते हुए कहा कि उनकी कमी कोई महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वे अपने खास अंदाज में हमेशा सक्रिय और जुड़े रहते हैं। यह टिप्पणी सुनकर सदन में मुस्कान की लहर दौड़ गई, जो इस गंभीर अवसर को कुछ पल के लिए सहज बना गई।

इसी क्रम में उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने उन्हें मृदुभाषी और विनम्र बताते हुए कहा कि वे अनुशासन के मामले में बेहद सख्त हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरिवंश ने अपने अवकाश के समय में भी युवाओं के साथ संवाद कर राष्ट्रीय मुद्दों को जीवंत बनाए रखा, जो लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राज्यसभा की भूमिका को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत की द्विसदनीय व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गहरी लोकतांत्रिक सोच का परिणाम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी परिवार में बड़े फैसलों से पहले बुजुर्गों की राय ली जाती है, वैसे ही राज्यसभा देश के लिए 'सेकेंड ओपिनियन' का काम करती है। जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, तो वहां होने वाली बहस और विचार-विमर्श से वह और अधिक मजबूत और परिपक्व बनकर सामने आता है।

प्रधानमंत्री ने संसद को एक 'खुला विश्वविद्यालय' बताते हुए कहा कि यहां केवल कानून नहीं बनते, बल्कि देश की विविधताओं, चुनौतियों और जटिलताओं को समझने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने कहा कि संसद में मिलने वाला अनुभव किसी भी औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक और गहरा होता है, जो एक जनप्रतिनिधि को राष्ट्रीय जीवन के लिए पूरी तरह तैयार करता है।

यह विदाई समारोह केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की उस निरंतरता का प्रतीक भी था, जिसमें व्यक्ति बदलते हैं, लेकिन संस्थाएं और उनके मूल्य कायम रहते हैं। विदा हो रहे सदस्यों के चेहरे पर जहां अपने संसदीय जीवन की यादें झलक रही थीं, वहीं प्रधानमंत्री के शब्दों ने उन्हें यह भरोसा भी दिया कि उनकी भूमिका और अनुभव आगे भी देश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे।

इस पूरे आयोजन ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, बल्कि संवाद, अनुभव और परंपराओं का संगम है, जहां हर विदाई एक नई शुरुआत का संकेत देती है।

संपादकीय

खनन पर हो मनन

सत्ताधीशों की इच्छा शक्ति की कमी और प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से खनन माफिया के हौसल बुलंद हैं। कहीं न कहीं नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बताता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों मसलन भूजल पुनर्भरण, मृदा-स्थिरता और जैव-विविधता संरक्षण जैसे जीवन रक्षक लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल, यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। वहीं इन क्षेत्रों में गाद जमाव का संकट भी गहरा जाता है। कालांतर इसके चलते जल निकासी के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने में आता है। यह सर्वविदित है कि एक बार इन पहाड़ियों को अवैध रूप से काटकर समतल कर दिया जाता है तो उसके मूल स्वरूप को फिर प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें उस क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक संरक्षण कवच हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट करने वाला विकास कालांतर आपदा का कारक बन सकता है।

दरअसल, यह ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र होता है जो निचले मैदानी इलाकों को बाढ़ और जल संकट से बचाता है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि इस बाबत जवाबदेह अधिकारियों द्वारा दलील दी जाती रही है कि इस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के आधार पर की जाती रही है। साथ ही यह भी सफाई दी जाती है कि ऐसी स्वीकृतियों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत तब उजागर हो जाती है जब स्थानीय लोग रात के समय होने वाले खनन कार्यों, निर्धारित सीमा से अधिक और बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कटाई होने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों की तमाम दलीलें खोखली ही साबित होती हैं। दरअसल,सवाल नियम-कानूनों की प्रभावकारिता का नहीं है बल्कि असली दिक्कत प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता की है। जो वस्तु-स्थिति से अवगत होने के बावजूद इन आपराधिक कृत्यों के प्रति आंखें मूंदे रहती हैं। दरअसल, खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को आपराधिक तत्वों व राजनेताओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि जब अवैध खनन के खिलाफ जमीनी स्तर पर निगरानी के बजाय महज कागजी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है तो अवैध खनन को संबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि यह अवैध खनन केवल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों के आसपास ही हो रहा है। पूरे भारत में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तमाम क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार पर्यावरण से जुड़े कानूनों की सीमाओं का उल्लंघन करता नजर आता है। अकसर खनन के लिये दिए गए परमिटों में अस्पष्टता और स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया जाता है। वह भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि आर्थिक गतिविधियां पारिस्थितिकीय नुकसान की कीमत पर नहीं चलायी जा सकती। फिर भी, जमीनी स्तर पर, प्रवर्तन एजेंसियां या तो शक्तिहीन दिखाई देती हैं या निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति उनमें नजर नहीं आती। वास्तव में अवैध खनन पर सिर्फ जुर्माना लगाने के बजाय प्रतिबंधित क्षेत्रों का सख्त सीमांकन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है।

आसान नहीं भाजपा की पंजाब में वर्चस्व की राह

> पंजाब के दौरों के दौरान, मोदी-शाह की जोड़ी ने न तो पंजाब के मूल मुद्दों को छुआ और न ही राज्य को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालने के लिए कोई सोची-समझी योजना पेश की। क्या भाजपा के पास पंजाब को उस 'आर्थिक संकट' से बचाने का वह दृष्टिकोण है, जिसकी कमी के लिए अतीत की सत्ताधारी पार्टियां कुख्यात रही हैं?

गत चौदह मार्च को मोगा में अपनी बहुप्रचारित रैली की शुरुआत करते हुए अमित शाह को पगड़ी पहने और सिखों का लोकप्रिय जयघोष करते देखना एक दिलचस्प नज़ारा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर सिख सभाओं में पगड़ी पहनकर आते हैं। जो कोई भी भाजपा नेताओं को सिखों को लुभाने के वास्ते ऐसे हास्यास्पद सुझाव देता है, उसे पंजाब से जुड़े किसी भी राजनीतिक मामले पर सलाह देने से स्थाई तौर पर रोक देना चाहिए।

यह कोई राज़ नहीं है कि भाजपा में फ़ैसले शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। यहां तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी ज़रूरी रहती है। जाहिर है, आने वाले विधानसभा चुनावों में चुनाव अकेले लड़ने के पार्टी के फ़ैसले का ऐलान करने से पहले अमित शाह ने सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे स्थानीय पार्टी नेताओं से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया था। जबकि कांग्रेस के ये दोनों पूर्व दिग्गज नेता सार्वजनिक तौर पर शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनावी गठबंधन करने की वकालत कर रहे थे। यह रवनीत सिंह बिट्टू ही थे जिन्होंने ऐसे किसी भी गठबंधन का ज़ोरदार विरोध किया है; ऐसे में अगर कल को उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए, तो कोई हैरत नहीं।

स्थानीय लोगों के साथ सार्थक संवाद के अभाव में, गृह मंत्री ने अपने भाषण में पसंदीदा अलगाव के मुद्दों में से एक का सहारा लिया—धर्मांतरण। भाजपा जिस 'बदलाव' का वादा कर रही है, यदि उसमें धर्मांतरण-विरोधी क़ानून भी शामिल है, तो चुनावी लिहाज़ से उसे कोई ख़ास सफलता नहीं मिलेगी। धर्मांतरण कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जो आम पंजाबियों को परेशान कर रहा हो। मामूली आर्थिक फ़ायदों के लिए ईसाई धर्म अपनाने वाले ग़रीब लोगों से समाज या राज्य

को कोई ख़तरा नहीं है। सबको अपने साथ लेकर चलने वाला पंजाब, धार्मिक आधार पर समाज में अलगाव से चुनाव जीतने के भाजपा के एजेंडे को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। आम तौर पर पंजाबी लोग अहंकारी नेताओं को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट देते हैं। उनकी कोई पसंदीदा पार्टी शायद ही कभी रही है। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली ज़बरदस्त जीत का श्रेय 'आप' के नेतृत्व से किसी बड़ी उम्मीद के बजाय, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के कुशासन के लिए उन्हें दी गई सज़ा को ज़्यादा जाता है। हो सकता है कि अब वे 'आप' से भी मोहभंग महसूस कर रहे हों, लेकिन वे इतने नाराज़ भी नहीं हैं कि उसे सत्ता से ही बेदख़ल कर दें।

सिख राजनीतिक विचारक और लेखक, अजमेर सिंह के अनुसार 'भाजपा ने हरियाणा में जाटों को अलग-थलग करके और गैर-जाटों को एकजुट करके चुनाव जीता था। पंजाब में भी वह यही रणनीति अपना सकती है—सिख जाट वोटों को बांटना और हिंदू, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वोटों को एकजुट करना'। डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख को पद्मश्री से सम्मानित करना और उसके बाद दलित बहुल इलाके में गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी का डेरा दौरा, ज़ाहिर तौर पर इसी रणनीति का हिस्सा हैं।

पंजाब के कुल वोटों में दलितों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है और जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुर—इन चार ज़िलों की 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों के नतीजों में वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दलितों के बीच रविदासिया समुदाय एक बड़ा हिस्सा है। भाजपा इसी समुदाय पर दांव लगा रही है। भाजपा की इस चुनावी रणनीति को एक और चीज़ से भी मदद मिल रही है—दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम की बार-बार पैरोल पर रिहाई। पंजाब के मालवा इलाके के कुछ हिस्सों में राम रहीम के बहुत सारे अनुयायी हैं और फिलहाल उसका पसंदीदा दल भाजपा है। ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरा आमतौर पर राजनीतिक रूप से तटस्थ रहता है।

भाजपा की दलितों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी शायद ही कामयाब हो जाए, क्योंकि पंजाब में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर बंटे हुए हैं और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। और इसीलिए भाजपा के लिए हरियाणा वाली सफलता को पंजाब में दोहराना मुश्किल होगा। यहां पर हालात पूरी तरह से उसके अनुकूल नहीं हैं। सिख आमतौर पर भाजपा से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि भाजपा की राजनीति भड़काऊ होती है, एजेंडा सांप्रदायिक केंद्रित होता है, और वह डेरों को संरक्षण देती है। सिखों का मुख्य सिद्धांत है 'सरबत दा भला' (सबका कल्याण)। पंजाबी स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष होते हैं। उग्रवाद के चरम पर होने के समय भी, गंभीर उकसावों के बावजूद, कोई बड़ा सांप्रदायिक विभाजन नहीं हुआ था।

सिखों को लुभाने के वास्ते, भाजपा ने पगड़ीधारी कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। राजनीति को धर्म से जोड़ते हुए, वह अक्सर गुरु तेग बहादुर और साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करती है, और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के बारे में दावे करती है; लेकिन इन सब बातों का कोई खास असर नहीं होता। इसके विपरीत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगातार दोहराया जाने वाला यह नज़रिया कि सिख भी हिंदुओं का ही हिस्सा हैं, इस समुदाय को विशेष रूप से नाराज़ करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कैंपस पर 'भगवा वर्चस्व' की कोशिशों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे।

भाजपा की सत्ता पाने की कोशिश का समर्थन किसानों और खेतिहर मज़दूरों द्वारा करने की संभावना कम ही है। पहले ही, तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साल भर चले विरोध प्रदर्शनों ने भाजपा नेतृत्व को बैकफुट पर धकेल रखा है। तिस पर 'बीज विधेयक', 'बिजली विधेयक' और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते ने उन्हें फिर से आंदोलन की राह पर ला खड़ा किया है। मोगा में अमित शाह किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बात कर सकते थे।

भाजपा की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां भी पंजाब को रास नहीं आती। इन नीतियों से आज़ादी के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा आर्थिक असमानता देखने को मिली है, और मुट्ठी भर 'गोदी सेठों' के हाथों में अकूत संपत्ति जमा हो गई है। धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना, समाज में भय को हवा देना, और लोगों का ध्यान भटकाने वाली राजनीति करना—ये सब भले ही व्यापक आर्थिक संकट को छिपा लें और चुनावी जीत दिला दें, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।

पंजाब के दौरों के दौरान, मोदी-शाह की जोड़ी ने न तो पंजाब के मूल मुद्दों को छुआ और न ही राज्य को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालने के लिए कोई सोची-समझी योजना पेश की। क्या भाजपा के पास पंजाब को उस 'आर्थिक संकट' से बचाने का वह दृष्टिकोण है, जिसकी कमी के लिए अतीत की सत्ताधारी पार्टियां कुख्यात रही हैं? क्या यह राज्य के सिर चढ़े उस कर्ज़ का बोझ हल्का करने में मदद कर सकती है, जो पिछले कई सालों में बेतरह ज्यादा खर्च, सोचे-समझे बिना कर्ज़ लेने और 'रेवड़ी योजनाओं' में पैसे की बर्बादी की वजह से जमा हो गया है?

तथापि सूबे में अपने अब तक के निराशाजनक प्रदर्शन और सत्ता तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली ढेरों रुकावटों के बावजूद, इस बार भाजपा की पंजाब में पैठ बनाने की कोशिश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाजपा की 'वोट जीतने वाली मशीन' की ताकत और पहुंच को कम करके नहीं आंकना चाहिए। इसके संगठनात्मक कौशल, आर्थिक ताकत, आरएसएस का समर्थन और एक 'अनुकूल' चुनाव आयोग, ये ऐसे बेजोड़ फायदे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। पार्टी नेतृत्व की राजनीतिक रणनीतियां और जातिगत समीकरण अक्सर मनचाहे नतीजे देते हैं।

प्रेरणा

बुद्धि का एक ऊंट: जहां समाधान सोच से जन्म लेता है

मानव जीवन में समस्याएँ उतनी कठिन नहीं होतीं, जितनी हमारी सोच उन्हें बना देती है। कई बार उलझन का कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है। इसी सत्य को उजागर करती है एक सूफी संत और उनके तीन शिष्यों की यह प्रसिद्ध कथा, जो केवल एक किस्सा नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ का दर्पण है। यह कथा बताती है कि जब बुद्धि, धैर्य और व्यापक दृष्टिकोण साथ आते हैं, तो असंभव दिखने वाली समस्या भी सरल समाधान में बदल जाती है।

एक सूफी संत थे, जिनके तीन शिष्य थे। ये तीनों उनके अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने गुरु की सेवा और शिक्षाओं में बिताया था। संत यह भली-भाँति जानते थे कि उनके जाने के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवनकाल में ही इस विषय को सुलझाने का प्रयास किया, ताकि उनके जाने के बाद उनके शिष्यों के बीच किसी प्रकार का मतभेद न हो।

संत के पास कुल सत्रह ऊंट थे। उन्होंने एक वसीयत तैयार की, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा कि उनके देहांत के बाद सबसे बड़े शिष्य को कुल ऊंटों का आधा हिस्सा दिया जाए, दूसरे शिष्य को एक-तिहाई हिस्सा और सबसे छोटे शिष्य को कुल ऊंटों का नौवां हिस्सा दिया जाए। देखने में यह बंटवारा न्यायपूर्ण और संतुलित प्रतीत होता था, लेकिन जब संत का देहांत हुआ और शिष्यों ने इस वसीयत को पढ़ा, तो वे गहरे असमंजस में पड़ गए। समस्या यह थी कि सत्रह ऊंटों का आधा आठ और आधा होता है, जिसे बांटना संभव नहीं था। इसी प्रकार एक-तिहाई और नौवां भाग भी पूर्णांक में नहीं आ रहे थे। तीनों शिष्य असमंजस में थे। वे सोचने लगे कि क्या उनके गुरु ने कोई भूल कर दी है, या फिर यह कोई ऐसी पहेली है जिसका उत्तर उन्हें स्वयं खोजना है। धीरे-धीरे उनके मन में चिंता और असंतोष उत्पन्न होने लगा।

परंतु तीनों शिष्य समझदार थे। उन्होंने आपस में विवाद करने के बजाय किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने का निर्णय किया। वे सभी महान बुद्धिमान और न्यायप्रिय हजरत अली के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या विस्तार से उनके सामने रखी और समाधान की प्रार्थना की।

हजरत अली ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, मानो वे पहले से ही इस समस्या का समाधान जानते हों। उन्होंने कहा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी की आवश्यकता है। फिर उन्होंने एक अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि वे अपनी ओर से एक ऊंट इन सत्रह ऊंटों में जोड़ देते हैं।

अब कुल ऊंटों की संख्या अठारह हो गई। इसके बाद उन्होंने वसीयत के अनुसार बंटवारा करना शुरू किया। सबसे बड़े शिष्य को अठारह का आधा, यानी नौ ऊंट दिए गए। दूसरे शिष्य को अठारह का एक-तिहाई, यानी छह ऊंट मिले। सबसे छोटे शिष्य को अठारह का नौवां हिस्सा, यानी दो ऊंट दिए गए। जब इन तीनों हिस्सों को जोड़ा गया, तो कुल संख्या सत्रह ही बनी—नौ, छह और दो मिलाकर सत्रह।

इस प्रकार सभी शिष्यों को उनका हिस्सा पूर्ण रूप से मिल गया, और किसी भी ऊंट को काटने या विभाजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद हजरत अली ने अपना जो एक ऊंट जोड़ा था, उसे वापस ले लिया। समस्या का समाधान इतना सरल और सहज था कि तीनों शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनके गुरु की वसीयत में कोई गलती नहीं थी, बल्कि वह उनकी समझ और धैर्य की परीक्षा थी।

यह कथा केवल एक चतुराई भरा गणितीय समाधान नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सिद्धांतों को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे देखने का सही तरीका अपनाना होता है। अक्सर हम किसी समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम अपनी सोच को थोड़ा व्यापक करते हैं, तो वही समस्या एक सरल अवसर में बदल जाती है।

इस कहानी में "एक ऊंट" केवल एक अतिरिक्त पशु नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस अतिरिक्त सोच का, उस नई दृष्टि का, जो हमें समस्या से बाहर निकलने में मदद करती है। जीवन में भी कई बार हमें ऐसे ही "एक ऊंट" की आवश्यकता होती है। यह "एक ऊंट" कभी धैर्य हो सकता है, कभी किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह, कभी आत्मचिंतन, तो कभी अपने दृष्टिकोण में बदलाव। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हों, तो हमें अहंकार को त्यागकर किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। तीनों शिष्यों ने यही किया। उन्होंने आपस में झगड़ने के बजाय एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर समाधान प्राप्त किया। यही समझदारी उन्हें विवाद से बचाकर संतोष की ओर ले गई।

इसके अलावा यह कहानी नेतृत्व और मार्गदर्शन के महत्व को भी दर्शाती है। एक सच्चा मार्गदर्शक वही होता है, जो जटिल परिस्थितियों को सरल बना दे और सबके हित में निर्णय ले। हजरत अली ने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि यह भी सिखाया कि समाधान हमेशा न्यायपूर्ण और व्यावहारिक होना चाहिए।

अंततः यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में समस्याएँ आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ें, तो हर कठिनाई का हल संभव है। यही जीवन की सच्ची बुद्धिमत्ता है—समस्याओं को अवसर में बदलना और हर उलझन में एक नया रास्ता खोज लेना।

दूषित जल : विकास के दावों पर एक गंभीर प्रश्न

अक्सर कहा जाता है कि जल ही जीवन है। किंतु यदि यही जल दूषित हो जाए तो क्या उसे जीवन का आधार कहा जा सकता है? सच तो यह है कि दूषित जल जीवन को बचाने के बजाय उसे संकट में डाल देता है। आज भारत सहित पूरी दुनिया में स्वच्छ जल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विडंबना यह है कि जिस देश में नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है और जल को जीवन का मूल तत्व माना जाता है, वहीं करोड़ों लोग आज भी स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। यह स्थिति केवल संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं नीतिगत कमजोरियों, प्रशासनिक उदासीनता और विकास के असंतुलित मॉडल की भी देन है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2019 में आरंभ हुआ जल जीवन मिशन इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। इस योजना का उद्देश्य था कि देश के हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त नदियों की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं भी शुरू की गईं। इन योजनाओं के कारण पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 2019 में केवल लगभग 16.7 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचता था, वहीं 2024 के अंत तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच गया। यह उपलब्धि निस्संदेह महत्वपूर्ण है, किंतु केवल पाइपलाइन बिछा देने भर से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। असली चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि जो पानी घरों तक पहुंच रहा है वह वास्तव में स्वच्छ और सुरक्षित भी हो। दुर्भाग्य से जल गुणवत्ता के मोर्चे पर स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं दिखाई देती। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पेयजल के नमूनों की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि बड़ी मात्रा में जल प्रदूषित पाया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लिए गए दूषित नमूनों में से केवल लगभग एक चौथाई को ही शुद्ध करने के प्रयास किए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग अब भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यह स्थिति हमारे विकास के दावों की तार्किकता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। यदि जल जैसे बुनियादी संसाधन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो विकास की उपलब्धियां अधूरी ही मानी जाएंगी। पेयजल की गुणवत्ता का संकट केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी यह समस्या बराबर देखने को मिलती है। महानगरों और बड़े शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पुरानी पाइपलाइन व्यवस्था और सीवेज प्रबंधन की कमजोरियों के कारण जल स्रोत लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। कई स्थानों पर पेयजल पाइपलाइन और सीवर लाइन एक-दूसरे के बेहद करीब बिछी हुई हैं। समय के साथ जब ये पाइपलाइन जर्जर हो जाती हैं तो सीवर का गंदा पानी पेयजल में मिल जाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाता है। हाल के वर्षों में कई शहरों में दूषित पानी के कारण लोगों के बीमार पड़ने और यहां तक कि मौत होने की घटनाएं सामने आई हैं। मध्यप्रदेश के इंदौर जैसे शहर में हुई ऐसी घटनाओं ने इस खतरे की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। यह विडंबना ही है कि जो शहर स्वच्छता के लिए देश में बार-बार अग्रणी स्थान प्राप्त करता रहा है, वहीं दूषित जल के कारण लोगों की जान जाने की घटनाएं सामने आती हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से यह चेतावनी देते रहे हैं कि अधिकांश बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है और दूषित जल इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। दस्त, उल्टी, टाइफाइड, हैजा और पीलिया जैसी जलजनित बीमारियां आज भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। इन बीमारियों का सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सीमित होती है। ऐसे में दूषित पानी केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह जाता, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले लेता है। जल प्रदूषण के पीछे कई कारण हैं। औद्योगिक कचरे का बिना उपचार के नदियों और जलाशयों में छोड़ा जाना एक बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त शहरों से निकलने वाला अनुपचारित सीवेज भी बड़ी मात्रा में जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश की सैकड़ों नदियों के अनेक नदी खंड जल गुणवत्ता के मानकों से नीचे पाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे जल स्रोत धीरे-धीरे प्रदूषण के गंभीर जाल में फंसते जा रहे हैं। दूसरी ओर, भूजल का अत्यधिक दोहन भी स्थिति को और जटिल बना रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक भूजल निकालने वाले देशों में अग्रणी है। अत्यधिक दोहन के कारण न केवल जल स्तर गिर रहा है, बल्कि कई स्थानों पर भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य हानिकारक रसायनों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है।

विकास की अंधी दौड़ ने भी इस संकट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेजी से फैलते शहर, बढ़ते उद्योग और बढ़ती आबादी जल संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहे हैं। लेकिन इसके समानांतर जल प्रबंधन की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। कई शहरों में सीवेज उपचार संयंत्रों की क्षमता पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में गंदा पानी सीधे नदियों और झीलों में पहुंच जाता है।

अभियान

विघ्नहर्ता का मातृत्व को प्रणाम: जब भगवान गणेश ने माता पार्वती को दिया अनंत आशीर्वाद

भारतीय पौराणिक परंपराओं में मां और पुत्र का संबंध केवल जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा, संस्कार और भावनाओं का अद्भुत संगम माना गया है। इस दिव्य संबंध का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण भगवान गणेश और माता पार्वती के बीच देखने को मिलता है। यह संबंध केवल ममता और स्नेह का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, आज्ञाकारिता, भक्ति और आशीर्वाद की एक ऐसी कथा है, जो युगों-युगों से मानव जीवन को दिशा देती आ रही है। इस कथा में एक ऐसा विलक्षण प्रसंग भी आता है, जब पुत्र स्वयं अपनी मां को वरदान देता है और उस क्षण में मातृत्व की महिमा एक नए शिखर पर पहुंच जाती है।

कथा की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं, जब माता पार्वती ने अपने तप और दिव्य शक्ति से एक बालक की रचना की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर के उबटन से उस बालक को जन्म दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक और कोई नहीं, बल्कि भगवान गणेश थे। यह जन्म सामान्य नहीं था, बल्कि मातृशक्ति की स्वायत्तता और सृजन की क्षमता का प्रतीक था। माता ने अपने पुत्र को न केवल जन्म दिया, बल्कि उसे अपने स्नेह, संस्कार और विश्वास से भी सींचा।

एक दिन जब माता स्नान के लिए गईं, तो उन्होंने बालक गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। यह आदेश केवल एक साधारण जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि यह विश्वास की परीक्षा थी। गणेश ने अपनी मां की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए यह निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में इस आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसी दौरान भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनके लिए माता की आज्ञा सबसे बड़ी थी।

इस घटना ने एक बड़ा संघर्ष उत्पन्न किया, जिसमें अंततः गणेश का मस्तक काट दिया गया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ, तो उनका क्रोध और शोक इतना प्रबल हो गया कि सृष्टि संतुलन खोने लगी। तब भगवान शिव ने स्थिति को संभालने के लिए एक हाथी का मस्तक लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही उन्होंने गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इस घटना ने गणेश को केवल जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया।

इस प्रसंग के बाद भगवान गणेश और माता पार्वती का संबंध और भी अधिक गहरा और आध्यात्मिक हो गया। माता ने अपने पुत्र को हर प्रकार का ज्ञान, संस्कार और जीवन का मार्गदर्शन दिया। वहीं गणेश ने भी एक आदर्श पुत्र की तरह हर शिक्षा को आत्मसात किया और अपनी मां के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया।

समय बीतने के साथ एक ऐसा अवसर आया, जब माता पार्वती ने अपने पुत्र की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए एक विशेष व्रत का अनुष्ठान किया। यह व्रत था संकष्टी चतुर्थी, जो आज भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। माता पार्वती ने इस व्रत को पूरे नियम और निष्ठा के साथ किया। उनके मन में केवल एक ही भाव था—अपने पुत्र का कल्याण और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।

भगवान गणेश अपनी माता के इस प्रेम और समर्पण को देखकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि एक मां अपने पुत्र के लिए किस प्रकार स्वयं को समर्पित कर देती है। यह केवल एक व्रत नहीं था, बल्कि मातृत्व की गहराई और निःस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था। इस भाव से अभिभूत होकर गणेश ने अपनी मां को एक अद्वितीय वरदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि जिस प्रकार आपने अपने पुत्र के लिए यह व्रत किया है, उसी प्रकार जो भी नारी इस संकष्टी चतुर्थी का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगी, उसे आपके समान मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। उसकी संतान गुणवान, आज्ञाकारी, यशस्वी और दीर्घायु होगी। साथ ही उसके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं विघ्नों का नाश करने वाला हूं।

यह वरदान केवल एक धार्मिक विधान नहीं था, बल्कि यह मातृत्व के भाव को संपूर्ण संसार में फैलाने का माध्यम बन गया। भगवान गणेश ने इस वरदान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि हर मां को अपने बच्चे के लिए वही सुरक्षा, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो, जो माता पार्वती को प्राप्त था। यह वरदान संतान की प्राप्ति से कहीं अधिक था—यह संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आश्वासन था।

इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष भी अत्यंत गहरा है। माता पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं और भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। जब शक्ति और बुद्धि का संगम होता है, तभी जीवन में संतुलन और पूर्णता आती है। इस कथा में यही संदेश निहित है कि मातृत्व केवल सृजन नहीं, बल्कि संरक्षण, मार्गदर्शन और आशीर्वाद का भी स्वरूप है।

आज भी इस कथा की स्मृति में देशभर की माताएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। वे दिनभर उपवास करती हैं, चंद्रमा के दर्शन के बाद गणेश जी की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस दिव्य वरदान का जीवंत प्रमाण है, जो एक पुत्र ने अपनी मां को दिया था।

यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि माता और संतान का संबंध केवल कर्तव्य और जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद का होता है। जहां माता अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार रहती है, वहीं संतान भी अपने आचरण और समर्पण से माता-पिता को गौरवान्वित करती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भगवान गणेश और माता पार्वती की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब भावनाएं शुद्ध होती हैं और समर्पण पूर्ण होता है, तब ईश्वर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने को बाध्य हो जाते हैं। यही इस कथा का सार है—मातृत्व की महिमा और पुत्र के प्रेम का अनंत विस्तार।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

युद्ध की आंच में भी अडिग भारत: 'जग लाडकी' की सुरक्षित वापसी ने दिखाया समुद्री शक्ति, कूटनीति और साहस का संगम

(जीएनएस)। पश्चिम एशिया में गहराते संकट और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत और गर्व की खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाला क्रूड ऑयल टैंकर जग लाडकी सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के एंकरिज पर पहुंच गया है। यह केवल एक जहाज की वापसी नहीं, बल्कि उस जटिल और जोखिम भरे भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की क्षमता, सतर्कता और रणनीतिक मजबूती का प्रतीक है, जहां हर क्षण अनिश्चितता और खतरे से भरा हुआ है।

बुधवार सुबह 5:51 बजे जब 'जग लाडकी' ने मुंद्रा के एंकरिज को छुआ, तब उसके साथ केवल 80,000 टन मर्बन कच्चा तेल ही नहीं था, बल्कि वह अपने साथ एक संदेश भी लेकर आया—भारत अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। यह कच्चा तेल, जो फुजैराह पोर्ट से लोड किया गया था, देश की रिफाइनरियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मौजूदा वैश्विक हालात में इसकी आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

लेकिन इस सफलता के पीछे एक बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक घटनाक्रम छिपा है। जहाज जब फुजैराह के सिंगल पॉइंट मूरिंग पर लोडिंग कर रहा था, उसी दौरान ईरान द्वारा फुजैराह ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला किया गया। इस हमले से वहां आग लग गई और लोडिंग ऑपरेशंस अस्थायी रूप से बाधित हो गए। यह घटना इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि क्षेत्र में हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। इसके बावजूद 'जग लाडकी' और उस पर सवार भारतीय नाविकों ने संयम और साहस का परिचय दिया और सुरक्षित बने रहे।

हमले के अगले ही दिन जहाज ने फुजैराह से प्रस्थान किया और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करते हुए भारत की ओर रवाना हो गया। यह वही समुद्री मार्ग है, जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माना जाता है और जहां किसी भी प्रकार का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

'जग लाडकी' का यह सफर इसलिए भी ऐतिहासिक बन जाता है क्योंकि यह युद्ध क्षेत्र से बिना किसी नुकसान के निकलने वाला तीसरा भारतीय ध्वज वाला जहाज है। इससे पहले एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी भी इसी खतरनाक रास्ते को पार कर चुके

हैं। इन दोनों जहाजों में कुल 92,712 टन एलपीजी लदा था, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'शिवालिक' जहां मुंद्रा पहुंच चुका है, वहीं 'नंदा देवी' कांडला बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया है।

इन सभी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के पीछे भारतीय नौसेना की सक्रिय भूमिका रही है। होर्मुज स्ट्रेट के पास बढ़ते खतरे को देखते हुए नौसेना ने इन जहाजों को एस्कॉर्ट प्रदान किया, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यह केवल एक सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है, जो अपने व्यापारिक और ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने पर आधारित है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की है, लेकिन भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग की गारंटी दी है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि भारत जैसे देशों के जहाजों को इस मार्ग से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। यह भारत और ईरान के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि ईरान ने कुछ जब्त टैंकरों की रिहाई के बदले सुरक्षित मार्ग की मांग की थी, लेकिन भारत ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। यह रुख इस बात का संकेत है कि भारत अपने सिद्धांतों और संप्रभुता से समझौता किए बिना भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है।

वर्तमान में पर्सियन गल्फ में 22 भारतीय ध्वज वाले मर्चेंट जहाज मौजूद हैं, जिनमें छह एलपीजी कैरियर, एक एलएनजी कैरियर और चार क्रूड ऑयल टैंकर शामिल हैं। इन जहाजों पर कुल 611 भारतीय नाविक सवार हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। शिपिंग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ईरान सहित अन्य संबंधित देशों से संपर्क में हैं, ताकि सभी जहाजों को सुरक्षित मार्ग मिल सके।

'जग लाडकी' की यह यात्रा केवल एक लॉजिस्टिक सफलता नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जिसमें भारत अपने ऊर्जा स्रोतों की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की निगरानी और वैश्विक संकटों में अपने नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देता है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि कैसे भारत ने सैन्य शक्ति, कूटनीति और प्रशासनिक समन्वय का प्रभावी उपयोग करते हुए एक संभावित संकट को सफलता में बदल दिया।

आज जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर रखे हुए है, तब 'जग लाडकी' की सुरक्षित वापसी एक सकारात्मक संकेत है। यह न केवल भारत के लिए, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक उदाहरण है, जो अपने नागरिकों और संसाधनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यह कहानी साहस, रणनीति और विश्वास की है—एक ऐसी कहानी, जो बताती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय और समन्वय से सफलता हासिल की जा सकती है।

स्पीपा के प्रशिक्षु अधिकारियों की गुजरात विधानसभा में अध्ययन यात्रा

विधानसभा की कार्यपद्धति की प्रत्यक्ष समझ के साथ मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष के साथ फोटो सेशन

(जीएनएस)। गांधीनगर : सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा), अहमदाबाद द्वारा उसके गांधीनगर परिसर में चल रहे प्रथम कॉमन फाउंडेशन कोर्स अंतर्गत प्रशिक्षु अधिकारियों के अध्ययन के लिए स्पीपा के महानिदेशक श्री हारित शुक्ला के प्रेरक मार्गदर्शन में प्रशिक्षुओं की गुजरात विधानसभा में अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरे में लगभग 50 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने विधानसभा के प्रश्नकाल का निरीक्षण कर राज्य की वैधानिक प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त की। इसके अलावा; विधानसभा के दैनिक कामकाज, चर्चा तथा निर्णय प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह उनके प्रशासनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रशिक्षु अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के साथ समूह तसवीर खिंचवाने का अवसर मिला।

इस अध्ययन दौरे के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने मंत्री श्रीमती मनीषा वकील, श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला से मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मंत्रियों ने लोक सेवा क्षेत्र में जिम्मेदारी, पारदर्शिता तथा लोक हित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अध्ययन यात्रा द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य के वैधानिक प्रशासन की कार्यपद्धति के बारे में जो व्यापक व प्रत्यक्ष समझ प्राप्त हुई है, वह भविष्य में उनके प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक होगी।

19,20 और 21 मार्च की रात्री में मीठाखली अंडरपास अस्थायी रूप से बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अहमदाबाद शहर में मीठाखली स्थित रेलवे अंडरब्रिज नं 12 के ऊपर से गुजरने वाली रेलवे ट्रैक पर आवश्यक मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। इस कार्य के अंतर्गत ट्रैक के नीचे एवं ऊपर के हिस्सों में पटरियों की स्ट्रेंथनिंग तथा जर्जर प्लेटों को हटाकर नई प्लेटों की स्थापना की जाएगी।

यह कार्य दिनांक 19, 20 एवं 21 मार्च, 2026 को केवल रात्रि अवधि (रात्रि 00:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) के दौरान किया जाएगा।

उक्त अवधि के दौरान मीठाखली अंडरपास के दोनों प्रवेश एवं निकास मार्ग वाहन यातायात के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

ट्रैफिक डायवर्जन विवरण:

मीठाखली छः रास्ता की ओर से अंडरपास के माध्यम से आश्रम रोड जाने वाला ट्रैफिक मीठाखली गांव के रास्ते आश्रम रोड एवं अन्य मुख्य मार्गों की तरफ से जा सकेगा।

आश्रम रोड की ओर से आने वाला ट्रैफिक आश्रम रोड स्थित बुट्टासिंह महादेव एवं खोडियार माता मंदिर के पास से नवरंगपुरा क्रॉसिंग होते हुए मीठाखली छः रास्ता एवं अन्य मार्गों की ओर जा सकेगा।

सभी नागरिकों से अनुरोध है कि उपरोक्त अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल अंतर्गत कनकपुरा यार्ड में प्रस्तावित नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भावनगर मंडल से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कनकपुरा यार्ड में रेल लाइनों के मध्य अतिरिक्त कनेक्शन स्थापित किए जाएंगे तथा दो लाइनों का लगभग 100 मीटर तक विस्तार किया जाएगा। इस कार्य से यार्ड की संचालन क्षमता एवं ट्रेनों की आवागमन सुगमता में सुधार होगा।

प्रभावित ट्रेनें निम्नानुसार हैं:

दिनांक 08 मई 2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस आंशिक रूप से परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी होकर संचालित होगी। यह ट्रेन जयपुर, अलवर एवं बांदीकुई स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

दिनांक 09 मई 2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20937 पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस आंशिक रूप से परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी होकर संचालित होगी। यह ट्रेन जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर एवं खैरथल स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

दिनांक 11 मई 2026 को मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19270 मुजफ्फरपुर–पोरबंदर एक्सप्रेस आंशिक रूप से परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी–रिंगस–फुलेरा होकर संचालित होगी। यह ट्रेन अलवर, बांदीकुई एवं जयपुर स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ट्रेन की अद्यतन जानकारी भारतीय रेल की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in, एनटीईएस (NTES) अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से अवश्य प्राप्त कर लें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 182 नई बसों का लोकार्पण किया

- गुजरात एसटी की जनसेवा प्रतिबद्धता का एक और नया माइलस्टोन
- मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों एवं पदाधिकारियों की प्रेरक उपस्थिति
- गुजरात एसटी निगम प्रतिदिन 8 हजार से अधिक बसों के काफिले के साथ 33 लाख किलोमीटर के संचालन से लगभग 27 लाख से अधिक यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन सेवा प्रदान करता है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के दिशादर्शन में गुजरात राज्य परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने 182 नई बसों के लोकार्पण से जनसेवा प्रतिबद्धता में एक नया माइलस्टोन जोड़ा है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली के करकमलों से राज्य के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक यानी कुल 182 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रियों की सेवा के लिए प्रस्थान कराने का गौरवशाली समारोह बुधवार को गांधीनगर में आयोजित किया गया। समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक तथा पदाधिकारी

भी सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इन नई बसों के चालकों को सांकेतिक रूप से चाबी अर्पित की।

आम आदमी के लिए आवागमन का सरल माध्यम गुजरात एसटी निगम दैनिक 8 हजार से अधिक बसों के काफिले के साथ 33 लाख किलोमीटर का संचालन कर 27 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं समयबद्ध बस सेवाएँ प्रदान करता है।

निगम विभिन्न तीज-त्योहारों तथा धार्मिक मेलों में अतिरिक्त बसों का संचालन कर राज्य की जनता को अपने परिवार के साथ तीज-त्योहार मनाने के लिए परिवहन सेवा-सुविधाएँ देता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष नई एसटी बसें खरीदने के लिए एसटी निगम को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत 2024-25 में 963 सुपर एक्सप्रेस, 550 गुर्जर नगरी, 100 स्लीपर बसें, 350 मीडी बसें सहित 1963 वाहन जनता की सेवा में समर्पित किए गए हैं।

पीपीपी आधार पर अत्याधुनिक 200 नई वॉल्वो तथा एसी बसों को भी संचालन में लाने का आयोजन किया गया है। समग्रतया 1963 नॉन-एसी तथा 200 एसी बसों को विभिन्न चरणों में जनता की सेवा में जोड़ा गया है। इनमें अब कुल 62 करोड़ रुपए के खर्च से इन 182 बसों को संचालन में लाने के लिए लोकार्पित किया गया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों ने इस अवसर पर लोगों का अभिवादन कर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। समारोह में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, परिवहन आयुक्त तथा जीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. राजेन्द्र कुमार और निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

सोना वायदा में 1616 रुपये और चांदी वायदा में 2112 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा 60 रुपये फिसला

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 162094.92 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 28774.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 133320.04 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2560.48 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16922.09 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 155658 रुपये के भाव पर खूलकर, 156075 रुपये के दिन के उच्च और 154201 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155985 रुपये के पिछले बंद के सामने 1616 रुपये या 1.04 फीसदी गिरकर 154369 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 1124 रुपये या 0.88 फीसदी गिरकर 126516 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 149 रुपये या 0.93 फीसदी गिरकर 15854 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 155989 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156156 रुपये और नीचे में 154306 रुपये पर पहुंचकर, 1653 रुपये या 1.06 फीसदी गिरकर 154377 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 156833 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156850 रुपये और नीचे में 155211 रुपये पर पहुंचकर, 156849 रुपये के पिछले बंद के सामने 1602 रुपये या 1.02 फीसदी गिरकर 155247 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 251498 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 254897 रुपये और नीचे में 249501 रुपये पर पहुंचकर, 253113 रुपये के पिछले बंद के सामने 2112 रुपये या 0.83 फीसदी गिरकर 251001 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 2940 रुपये या 1.13 फीसदी घटकर 256126 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 2646 रुपये या 1.02 फीसदी गिरकर 256506 रुपये प्रति

- कमोडिटी वायदाओं में 28774.87 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 133320.04 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 16922.09 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 2390.14 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 7.95 रुपये या 0.68 फीसदी गिरकर 1168.55 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 2.2 रुपये या 0.69 फीसदी औंधकर 317.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 90 पैसे या 0.26 फीसदी की नरमी के साथ 340 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

जबकि सीसा मार्च वायदा 80 पैसे या 0.43 फीसदी टूटकर 187.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8946.62 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 8771 रुपये के भाव पर खूलकर, 8896 रुपये के दिन के उच्च और 8501 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 60 रुपये या 0.68 फीसदी गिरकर 8811 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 47 रुपये या 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 8807 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 277.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 278 रुपये और नीचे में 271.4 रुपये पर पहुंचकर, 280.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 5 रुपये या 1.78 फीसदी गिरकर 275.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 5.1 रुपये या 1.81 फीसदी की गिरावट के साथ 276 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 968 रुपये पर खूलकर, 1.4 रुपये या 0.14 फीसदी औंधकर 966.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 10756.56 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6165.54 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1593.99 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 440.17 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 4.85 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 349.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7396.68 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1521.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.76 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 2.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11265 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 63428 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32461 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 474758 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 67362 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6917 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20853 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 79623 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 23995 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 31137 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 10.3 रुपये की गिरावट के साथ 929 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.85 रुपये की गिरावट के साथ 8.6 रुपये हुआ। सोना मार्च 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 355 रुपये की गिरावट के साथ 400 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1235 रुपये की गिरावट के साथ 8824.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.47 रुपये की गिरावट के साथ 3.82 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 67 पैसे की नरमी के साथ 0.65 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 14.1 रुपये की गिरावट के साथ 219.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.8 रुपये की बढ़त के साथ 7.65 रुपये हुआ।

सोना मार्च 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 281.5 रुपये की बढ़त के साथ 777 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 214.5 रुपये की बढ़त के साथ 576 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 92 पैसे के सुधार के साथ 7.54 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 64 पैसे के सुधार के साथ 2 रुपये हुआ।

ऐतिहासिक बंदरगाह से औद्योगिक शक्ति तक, सूरत की विकास यात्रा ने रचे कई नए

- सूरत दुनिया के लगभग 90% प्राकृतिक हीरों और 25% लैब-निर्मित हीरों की प्रोसेसिंग करता है।
- करीब 6,000 डायमंड यूनिट्स, जिनमें 70% MSMEs रोजगार और निर्यात का बड़ा आधार
- 16वीं सदी का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह आज आधुनिक औद्योगिक और टेक्सटाइल हब में तब्दील।
- Growth Hub पहल के तहत सूरत को इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट के पायलट के रूप में चुना गया।
- सूरत आर्थिक क्षेत्र (SER) मास्टर प्लान के जरिए पूरे दक्षिण गुजरात को ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने का लक्ष्य।

(जीएनएस)। गांधीनगर : सूरत, गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर और भारत का नौवां सबसे बड़ा शहर,

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के कुशल नेतृत्व में एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित यह शहर हीरा और रेशम उद्योग में अपनी उत्कृष्टता के कारण 'डायमंड सिटी' और 'सिल्क सिटी' जैसे उपनामों से प्रसिद्ध है। भारत के सबसे प्रगतिशील और उद्यमशील शहरों में से एक, सूरत गर्व से गुजरात की समृद्ध विरासत और दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। इस शहर ने निरंतर अवसरों को उपलब्धियों में बदलते हुए मजबूत बुनियादी ढांचा, कुशल नागरिक सेवाएं और एक गतिशील औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। अपनी रणनीतिक तटीय स्थिति के कारण, सूरत भारत का एक महत्वपूर्ण पश्चिमी प्रवेश द्वार बन गया। 16वीं शताब्दी में यह भारत और कई पश्चिमी देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण

व्यापारिक कड़ी के रूप में उभरा।

सूरत बंदरगाह के रणनीतिक महत्व के कारण ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच शक्तियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और सहभागिता बढ़ी, जिससे शहर का व्यापारिक नेटवर्क विस्तृत हुआ। उसी समय, यह शहर जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी था। इस प्रकार, यह अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों में से एक बन गया। आज सूरत हीरा के आभूषण बनाने और पॉलिशिंग

का अग्रणी केंद्र है, साथ ही एशिया के सबसे बड़े वस्त्र केंद्रों में से भी एक है, जो वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता प्रदान करने में सटीकता, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

सूरत विश्व के लगभग 90% प्राकृतिक हीरों और लगभग 25% लैब-निर्मित हीरों का प्रसंस्करण करता है। यहां लगभग 6,000 हीरा काटने और पॉलिशिंग इकाइयां हैं, जिनमें से लगभग 70% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) हैं। शहर का मजबूत MSME क्षेत्र, कुशल कार्यबल और व्यापार-अनुकूल वातावरण इसे गुजरात की आर्थिक शक्ति का प्रमुख योगदानकर्ता बनाते हैं। आधुनिक शहरी नियोजन, बेहतर कनेक्टिविटी और सतत विकास पहलों ने सूरत को भारत के सबसे तेजी से विकसित और रहने योग्य शहरों में शामिल किया है। आगामी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (VGRC) के आयोजन के साथ सूरत एक बार फिर अपनी प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है। विरासत में जड़ें और महत्वाकांक्षा से प्रेरित यह शहर साझेदारी और समृद्धि के नए अवसर खोलता जा रहा है। अपने अटूट संकल्प और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ, सूरत गुजरात और देश के विकास के अगले दौर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नीति आयोग की ग्रोथ हब (G Hub) पहल के तहत, सूरत को प्रमुख शहर क्षेत्रों में से एक के रूप में चुना गया है, जहां एकीकृत क्षेत्रीय विकास के नए मॉडल का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और परस्पर जुड़े जिलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना है। इस दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए, नीति आयोग के सूरत आर्थिक क्षेत्र (SER) आर्थिक मास्टर प्लान ने दक्षिण गुजरात क्षेत्र जिसमें सूरत, भरूच, नवसारी, तापी, डांग और वलसाड शामिल हैं को 2047 तक एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आर्थिक केंद्र में परिवर्तित करने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी

मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल एवं विभिन्न रेल परियोजनाओं का तेजी से कार्य प्रगति पर
मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल: वायाडक्ट, पियर और ट्रैक बिछाने का काम तेजी से जारी
सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी: देशलपार-हाजीपीर और वायोर-लखपत जैसे मार्गों पर सर्वेक्षण

(जीएनएस)। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में भारतीय रेलवे की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में रेल अवसंरचना के विकास को अभूतपूर्व गति दी जा रही है।

रेल मंत्री ने गुजरात से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना पर तेजी से कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अंतर्गत 300 किलोमीटर से अधिक वायाडक्ट का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि पियर निर्माण, ट्रैक बिछाने तथा स्टेशनों के विकास का कार्य निरंतर जारी है। इसके साथ ही भारत की पहली अंडर सी रेल सुरंग पर भी कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत 435 किलोमीटर फाउंडेशन कार्य, 338 किलोमीटर गर्डर इंस्टॉलेशन तथा 168 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के साथ ओएचई इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वापी, बिलिमोरा, सूरत तथा बीकेसी सहित कई स्टेशनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

रेल मंत्री ने जानकारी दी कि कई नदियों पर पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है तथा भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद एवं साबरमती क्षेत्रों में कार्य तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।

सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं। कच्छ क्षेत्र में देशलपार–हाजीपीर तथा वायोर–लखपत के बीच नई रेल कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

भारतीय रेलवे वर्तमान में अभूतपूर्व विस्तार और आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है, जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 में 2.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड बजटीय आवंटन

से सशक्त बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, जबकि बीते 2 वर्षों में 1.43 लाख सीधी नियुक्तियां की गई हैं।

सुरक्षा अवसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए आरओबी और आरयूबी की संख्या लगभग 4,000 से बढ़कर 14,000 हो गई है। ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का विस्तार भी 1,500 किलोमीटर से बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। सुरक्षा तकनीक पर चर्चा करते हुए, उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लगभग 3,000 किलोमीटर के नेटवर्क को पहले ही इसके दायरे में लाया जा चुका है, जबकि करीब 20,000 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है और लगभग 8,000 रेल इंजनों में इसे लगाने की योजना है।

रेल मंत्री ने बताया कि एलएचबी कोचों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हाल के वर्षों में लगभग 48,000 कोच जोड़े गए हैं। लोकोमोटिव उत्पादन लगभग 12,000 यूनिट तक पहुंच गया है तथा वैगनों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है।

टनल निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। वर्ष 2014 तक जहां लगभग 125 किलोमीटर टनल का निर्माण हुआ था, वहीं उसके बाद 486 किलोमीटर अतिरिक्त टनल बनाई गई हैं, जिससे पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क में सुधार हुआ है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के निर्माण में भी व्यापक प्रगति हुई है। लगभग 2,800 किलोमीटर कॉरिडोर का कार्य पूरा हो चुका है, जिन पर प्रतिदिन लगभग 480 मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं।

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जनरल कोचों की शुरुआत की गई है, जिनमें वर्ष 2024-25 में लगभग 1,250 और 2025-26 में करीब 860 कोच शामिल हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हैं तथा 60 अमृत भारत ट्रेनें किफायती लंबी दूरी की यात्रा सुविधा प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 133 अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

उन्होंने बताया कि 75 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया विकसित किए जा रहे हैं तथा यात्रियों की सुविधा के लिए 1,200 से अधिक नई ईएमयू/मेमू सेवाएं शुरू की गई हैं।

रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक शुरू किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1,300 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें से करीब 180 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 500 स्टेशन उन्नत चरण में हैं।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा पश्चिम रेलवे की महिला कर्मचारियों का सम्मान

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा पश्चिम रेलवे की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों को उनके समर्पण, प्रतिबद्धता एवं अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करने हेतु एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्यक्रम 16 मार्च, 2026 को सौहार्दपूर्ण एवं उत्सवपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया, जिसमें महिला रेल कर्मचारी एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन के सदस्य उपस्थित थीं। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती ईशा मलिक ने विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली 57 महिला कर्मचारियों को कार्यकारी समिति के सदस्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम में महिला कर्मचारियों के संगठन के सुचारु संचालन में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित किया गया तथा उच्चस्तर की व्यावसायिकता बनाए रखने में उनके निरंतर प्रयासों की सराहना की गई। यह सम्मान समारोह उनके समर्पण, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक रहा।

सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती मलिक ने संगठन में महिला कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की तथा उनकी इस क्षमता की प्रशंसा की कि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए कार्य एवं निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। उन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को कार्यस्थल से आगे बढ़कर बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। समान अवसरों के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग दिया जाना चाहिए तथा उन्हें आत्मविश्वासी, स्वतंत्र एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।

यह कार्यक्रम न केवल महिला कर्मचारियों की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए समावेशी, सहयोगपूर्ण एवं सशक्त कार्य वातावरण निर्माण के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को भी पुनः रेखांकित करता है।

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु अहमदाबाद मंडल में आधुनिक रसोई उपकरणों की आपूर्ति

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने एवं गैस पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मंडल के विभिन्न रनिंग रूमों एवं प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक विद्युत-आधारित रसोई उपकरणों की आपूर्ति का कार्य निरंतर प्रगति पर है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि कार्यस्थलों पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी सिद्ध हो रही है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, आज भुज एवं सनोसरा स्थित रनिंग रूमों सहित प्रशिक्षण केंद्रों को सुदृढ़ एवं उन्नत रसोई सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से ओवन, कुकर, इंडक्शन कुकटॉप, रोटी तवा, ग्लास मिक्सिंग बाउल तथा पतीलों की आपूर्ति की गई। इससे संबंधित इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं ऊर्जा-कुशल खानपान सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही भोजन तैयारी की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक, त्वरित एवं आधुनिक बनेगी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा इसी प्रकार मंडल के अन्य प्रमुख रनिंग रूमों जैसे अहमदाबाद, साबरमती, गांधीधाम, विरमगाम सहित प्रशिक्षण केंद्रों में भी चरणबद्ध तरीके से इन आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल कार्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।